





# यूबे के राजनीतिक दलों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

## लोक चुनाव अधिकारी तीन चरणों में और 21 दिनों के भीतर हों : जदयू

पटना। जदयू के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजीव रंजन सिंह, बिहार जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार शर्मा, राजसभा सदस्य अनिल हेगडे, राष्ट्रीय महासचिव संजय पाण्डे अफालक अहमद खान तथा प्रदेश महासचिव मुख्यालय प्रभारी चंदन कुमार सिंह संघ शामिल थे। बैठक के दौरान जदयू ने अपने सुझाव में कहा कि लोकसभा चुनाव कर्म अवधि और अधिकारी तीन चरणों में कराए जाएं। इन तीनों अवधियों के चुनाव 21 दिनों के भीतर हो जाएं तो बेहतर होगा। इससे न केवल मतदाताओं को अप्रैल-मई की भीषण गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि संसाधनों की भी बेचत होगी और जन-जीवन असत्-व्यस्त नहीं होगा। अपने अन्य सुझाव में जदयू ने कहा कि चुनाव के दिन असामिक तत्व गणेश-गुरुओं को मतदान करने से रोक सकते हैं और बूथ कञ्जा करने की ओर आंकड़ों की ओर आयोग को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील बैठकों पर सक्षम व पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती हो। चुनाव-आयोग को दिए गए अपने ज्ञापन में जदयू ने यह भी कहा कि जदयू प्रारंभ से ईवीएम और बीवीपैट के पक्ष में रही है। चुनाव-प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पार्टी पूर्ववत् इसका समर्थन करती है।

## राजद ने 20 सूत्री ज्ञापन सौंपा, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग

पटना। राजद का तीन सदस्यों प्रतिनिधिमंडल ने भारत निवाचन आयोग के मुख्य निवाचन आयुक्त से मिलकर आगामी लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रेस उच्चाय वृषभ पेल, प्रेस्या चित्तरंजन गणन एवं मुख्यालय प्रभारी मुंद्रुद सिंह शामिल थे। राजद प्रवक्ता एवं प्रतिनिधिमंडल की ओर से 20 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निवाचन आयुक्त से मिलकर राजद की ओर से राजद ने 20 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल के द्वारा निवाचन आयुक्त से आगामी लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से कराने, भी भी पैट से निकले पर्वी को मतदाता को दिखाने और सभी मतदान केन्द्रों के भीषी पैट पर्वियों को सोलांबद वॉक्स में रखकर इंवीएम के साथ ही उसकी भी गिनती करने के बालंबन एवं प्रतिनिधिमंडल के बालंबन एवं पर्वियों की गिनती शुरू करने के बालंबन एवं प्रतिनिधिमंडल के बालंबन एवं पर्वियों की गिनती से निवाचित करने, यात्रा भी संभव है। इंवीएम की गिनती से निवाचित करने, यात्रा भी संभव है। अप्रैल से ईवीएम एवं बीवीपैट को चुनाव कराने के लिए पार्टी पूर्ववत् इसका समर्थन करती है।

## लोक शक्तियों ने अनुमति के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान हो : भाजपा



### भाजपा ने सौंपा 22 सूत्री मांग प्र

पटना, 20 फरवरी। बिहार भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज पटना में भारत निवाचन आयोग की बिहार आई टीम के समक्ष लोकसभा क्षेत्रों में अनुमति के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने का सुझाव दिया है। प्रतिनिधिमंडल में विधायक नितिन नवीन, संजय सरावनी तथा चुनाव प्रधान विधायक, भाजपा के प्रदेश संस्कृतकर्ता सम्पन्न शामिल थे। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निवाचन आयुक्त से मिलकर भाजपा की ओर से 22 सूत्री सूझाव और मार्ग वर्त सौंपा। सुझाव पत्र में कहा गया है कि मतदाता सूची में एक ही मतदाता का नाम अपने विधान सभा के अलावा पास के कई अन्य विधान सभा क्षेत्रों में है। इनकी सूचन जाँच करायी जाय और दोहरी एवं तिहाई प्रविष्टि को समाप्त की जाए। भाजपा ने मतदाताओं को मतदान केन्द्रों की जानकारी के लिए एसएसएस एवं कराने के सुझाव देते हुए एसएसएस के माध्यम से मतदाता पर्याप्त उत्तराधिकार कराने के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी सुझाव दिया है। इससे अलावा भाजपा ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अनुमति के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी बेकालत की है। भाजपा तकनीकी या संवर्धित विधायकों की जानकारी के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी बेकालत की है। भाजपा ने चुनाव आयोग से शेष प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने, स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान केन्द्र पर किसी भी तरह के ढंके हुए चेहरे वाले मतदाताओं के चेहरों का मिलान चैक्य करने और पहचान सुनिश्चित करने एवं टाल करने के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी सुझाव दिया है। भाजपा ने दियारा एवं टाल क्षेत्र में खुड़सावर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती तथा नदी मार्ग पर चुनाव के दौरान नदी वाले इलाकों में नावों की संधन जाँच कराने, केंद्रीय पारा मिलिंटी फोटो की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं टाल क्षेत्र में खुड़सावर सुरक्षाकर्मियों की जानकारी के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी सुझाव दिया है।



जयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री संजय झा राजसभा सदस्य के लिए हुए निर्वाचित। निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आभार व्यक्त किया। इस दौरान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, विधानपरिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर व पूर्व मंत्री अशोक चौधरी मौजूद थे।

## मनोज झा एवं संजय यादव निर्विदेश रास्ते पर चुनाव आयोग से लगातार एक जगह पर पदस्थापित चुनाव पदाधिकारियों को तकलीफ स्थानात्तरित करने के तांत्र

पटना, प्रातः किरण संवाददाता

राष्ट्रीय नायन दल के राज्य कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानन्द सिंह के हाथों दोनों उम्मीदवार प्रेरणा की ओर से किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानन्द सिंह के लिए चुनाव आयोग से शेष प्रतिशत मतदाताओं को फोटो की जारी करने, स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान केन्द्र पर किसी भी तरह के ढंके हुए चेहरे वाले मतदाताओं के चेहरों को नाम देने और पहचान सुनिश्चित करने एवं टाल करने के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी सुझाव दिया है। इससे अलावा भाजपा ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अनुमति के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी बेकालत की है। भाजपा ने चुनाव आयोग से शेष प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने, स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी बेकालत की है। भाजपा ने दियारा एवं टाल क्षेत्र में खुड़सावर सुरक्षाकर्मियों की जानकारी के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी सुझाव दिया है। इससे अलावा भाजपा ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अनुमति के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी बेकालत की है। भाजपा ने चुनाव आयोग से शेष प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने, स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी बेकालत की है। भाजपा ने दियारा एवं टाल क्षेत्र में खुड़सावर सुरक्षाकर्मियों की जानकारी के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी सुझाव दिया है। इससे अलावा भाजपा ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अनुमति के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी बेकालत की है। भाजपा ने चुनाव आयोग से शेष प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने, स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी बेकालत की है। भाजपा ने दियारा एवं टाल क्षेत्र में खुड़सावर सुरक्षाकर्मियों की जानकारी के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी सुझाव दिया है। इससे अलावा भाजपा ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अनुमति के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी बेकालत की है। भाजपा ने चुनाव आयोग से शेष प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने, स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी बेकालत की है। भाजपा ने दियारा एवं टाल क्षेत्र में खुड़सावर सुरक्षाकर्मियों की जानकारी के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी सुझाव दिया है। इससे अलावा भाजपा ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अनुमति के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी बेकालत की है। भाजपा ने चुनाव आयोग से शेष प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने, स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी बेकालत की है। भाजपा ने दियारा एवं टाल क्षेत्र में खुड़सावर सुरक्षाकर्मियों की जानकारी के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी सुझाव दिया है। इससे अलावा भाजपा ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अनुमति के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी बेकालत की है। भाजपा ने चुनाव आयोग से शेष प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने, स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी बेकालत की है। भाजपा ने दियारा एवं टाल क्षेत्र में खुड़सावर सुरक्षाकर्मियों की जानकारी के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी सुझाव दिया है। इससे अलावा भाजपा ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अनुमति के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी बेकालत की है। भाजपा ने चुनाव आयोग से शेष प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने, स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान कराने की भी बेकालत की है। भाजपा ने





## राजनीति से प्रेरित कार्टवाई

कांग्रेस के बैंक खाते पर हुई कार्रवाई का उसकी गतिविधियों पर गहरा असर पड़ेगा। क्या आय कर विभाग यही चाहता है? जिस समय विषय के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पहले से संदिग्द है, ऐसे सवाल उठना अस्वाभाविक नहीं है। कांग्रेस के खाते का संचालन जिस समय और जिस तरह से रोका गया, उसे पहली नज़र में राजनीति से प्रेरित कार्रवाई ही माना जाएगा। यह कार्रवाई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मामले में सुखमिं कोर्ट के फैसले आने के ठीक अग्रणी दिन की गई। इसने निर्णय से साताधारी असहज स्थितिया पैदा हुई। इससे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के जरिए भाजपा को असामान्य रूप से मिले अधिक चर्चे और उसके स्रोत का मुद्दा चर्चा में आया। उसके ठीक अगले दिन देश की प्रमुख विषयों की पार्टी पर ऐसी कार्रवाई के कामसर पर खड़ा हुआ। सवाल उठाया कि जिसके बाहर बताने की काशिश की गई है तब विषय के चर्चे में भी खड़ा है? यह कर विभाग की इस कार्रवाई के तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है। यह कदम 2018-19 में कांग्रेस को मिले चर्चे के सिलसिले में यानी अब पांच साल बाद उठाया गया है। तब पार्टी तय तारीख (31 दिसंबर 2019) तक इकम टैक्स जमा नहीं करा पाया। उसने 45 दिन देर से इसे जमा कराया। रिटर्न में पार्टी ने बताया कि गुजरे साल में 199 करोड़ रुपये का चंदा उसके बैंक खाते में आया, जबकि 14 लाख 40 हजार रुपये उसके पास नकदी में हैं, जो उसे पार्टी संसदीय और विभागीयों के से मिले हैं। आय कर विभाग ने नकदी का कम को विसंगति (डिस्क्रेप्शनी) बताया है, जबकि 45 की हुई देर को लोकर 21 करोड़ रुपये की जमार्ना लगा दिया है। यह कार्रवाई लोकर 210 करोड़ रुपये की जमार्ना लगा दिया है। खाते के संचालन पर रोक को जब कांग्रेस ने अपीलीय प्रचार में चुनौती दी, तो पार्टी ने खाते के संचालन से रोक तो हटा दी, लेकिन शर्त लगा दी कि कांग्रेस को 155 करोड़ रुपये खाते में रखना होगें। पार्टी का मुताबिक उसके पास इसके अतिरिक्त रकम नहीं है। यानी व्यावरणीक रूप में खाते का इसका रामबाल कर पाएगी। जाहिर है, पार्टी की गतिविधियों पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। क्या आय कर विभाग का यही मकसद है? जिस समय विषय के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पहले से संदिग्द है।

## केजरीवाल की कहानियों का अंत नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वामें और उनकी कहानियों का अंत ही नहीं हो रहा है। उनकी सरकार ने एक बार पर विभागनसभा में विभाग सम पेश कर दिया। किसी ने उनके बहुत अधिक विभाग नहीं जाहिर किया था और उनकी से उनकी सरकार को खतरा दिख रहा था। 70 सदस्यों की राज्य विधानसभा में केजरीवाल की पार्टी के 62 विधायक हैं। उन्हें तीन चौथाई से भी ज्यादा बहुमत है। फिर भी वह तीसरा मोक्षा है, जबकि उन्होंने विभाग समत बहसित करने का द्वारा रक्षा रखा है। पहले भी उन्होंने एरोप लाया था कि उनके विधायकों को 20 करोड़ रुपए देने की आरोप लाया था कि विभाग के बाद उन्होंने विभागनसभा के सत्र में बजट टाल दिया और विभाग मत पेश कर दिया। अब फिर आरोप लाया है कि सत्र विभाग को 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश दी जा रही है। यह सच कि विभाग को बाल जारी करने के टूटूरे से भी केजरीवाल की सरकार पर खिड़ा ही है। कि वे दिल्ली में बयान देने के बाद औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं। किसी व्यक्ति का नाम लें, जिसने पैसे की पेशकश की या कोई फोन नंबर ही बताएं कि इस नंबर से फोन करें पेशकश की गई थी। लेकिन उनकी पार्टी ने न कोई स्कूल झटका कर दिया है। लेकिन विभागनसभा के सत्र में बजट टाल दिया और विभाग मत पेश कर दिया।

## संदेशखाली की दरिदगी

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली इलाके के हालात को देख सुन कर ऐसा लगता है कि कि मुख्यमंत्री ममता बनजी ने उन्हें पहले ही देखा, भोगा और अनुभव किया है। संदेशखाली पर जितनी रपटें और विभेषण सामने आए हैं, उनके मद्देनजर आश्रम होता है कि 2011 से वहाँ ह्यावर्दिन के अत्याचार, जीव उत्तीर्ण और भूमि पर जबरन कब्जों के सिलसिले जारी रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें झटक करार दे रहे हैं। उन्होंने विभागनसभा में कहा है कि संदेशखाली में आरएसपी का अड़ा है और वही औरतों को उकसाओं और बरगता कर रहा है। यह सच कि हालांकां चेहरे ढक कर बोली हैं, क्योंकि उन्हें ह्यावर्दिनी राक्षसों का खौफ है। दुर्मार्ग और विभागनसभा के खिलाफ कार्रवाई की जारी रही है। औरतों की आरोप लाया जाता है कि उनके विधायकों को 20 करोड़ रुपए देने की आरोप लाया था कि उनके विधायकों को बाल जारी करने विभागनसभा मत पेश कर दिया। अब फिर आरोप लाया है कि सत्र विभाग को 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश भाजपा ने की है और सरकार गिराया जाता है। दाता की जारी रही है। तब विभाग के टूटूरे से भी केजरीवाल की दाता की जारी रही है। तब विभाग के खिलाफ कार्रवाई की जारी रही है।

दिल्ली पुलिस उन्हें पूछी है कि वे दिल्ली में बयान देने के बाद औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं। किसी व्यक्ति का नाम लें, जिसने पैसे की पेशकश की या कोई फोन नंबर ही बताएं कि उनकी विभागनसभा के सत्र में बजट टाल दिया और विभाग मत पेश कर दिया।

केजरीवाल की कहानियों का अंत नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वामें और उनकी कहानियों का अंत ही नहीं हो रहा है। उनकी सरकार ने एक बार पर विभागनसभा में विभाग सम पेश कर दिया। किसी ने उनके बहुत अधिक विभाग नहीं जाहिर किया था और उनकी से उनकी सरकार को खतरा दिख रहा था। 70 सदस्यों की राज्य विधानसभा में केजरीवाल की पार्टी के 62 विधायक हैं। उन्हें तीन चौथाई से भी ज्यादा बहुमत है। फिर भी वह तीसरा मोक्षा है, जबकि उन्होंने विभाग समत बहसित करने का द्वारा रक्षा रखा है। पहले भी उन्होंने एरोप लाया था कि उनके विधायकों को 20 करोड़ रुपए देने की आरोप लाया था कि उनके विधायकों को बाल जारी करने विभागनसभा मत पेश कर दिया। अब फिर आरोप लाया है कि सत्र विभाग को 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश भाजपा ने की है और सरकार गिराया जाता है। दाता की जारी रही है। तब विभाग के टूटूरे से भी केजरीवाल की सरकार पर खिड़ा ही है। कि वे दिल्ली में बयान देने के बाद औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं। किसी व्यक्ति का नाम लें, जिसने पैसे की पेशकश की या कोई फोन नंबर ही बताएं कि उनकी विभागनसभा के सत्र में बजट टाल दिया और विभाग मत पेश कर दिया।

केजरीवाल की कहानियों का अंत नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वामें और उनकी कहानियों का अंत ही नहीं हो रहा है। उनकी सरकार ने एक बार पर विभागनसभा में विभाग सम पेश कर दिया। किसी ने उनके बहुत अधिक विभाग नहीं जाहिर किया था और उनकी से उनकी सरकार को खतरा दिख रहा था। 70 सदस्यों की राज्य विधानसभा में केजरीवाल की पार्टी के 62 विधायक हैं। उन्हें तीन चौथाई से भी ज्यादा बहुमत है। फिर भी वह तीसरा मोक्षा है, जबकि उन्होंने विभाग समत बहसित करने का द्वारा रक्षा रखा है। पहले भी उन्होंने एरोप लाया था कि उनके विधायकों को 20 करोड़ रुपए देने की आरोप लाया था कि उनके विधायकों को बाल जारी करने विभागनसभा मत पेश कर दिया। अब फिर आरोप लाया है कि सत्र विभाग को 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश भाजपा ने की है और सरकार गिराया जाता है। दाता की जारी रही है। तब विभाग के टूटूरे से भी केजरीवाल की सरकार पर खिड़ा ही है। कि वे दिल्ली में बयान देने के बाद औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं। किसी व्यक्ति का नाम लें, जिसने पैसे की पेशकश की या कोई फोन नंबर ही बताएं कि उनकी विभागनसभा के सत्र में बजट टाल दिया और विभाग मत पेश कर दिया।

केजरीवाल की कहानियों का अंत नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वामें और उनकी कहानियों का अंत ही नहीं हो रहा है। उनकी सरकार ने एक बार पर विभागनसभा में विभाग सम पेश कर दिया। किसी ने उनके बहुत अधिक विभाग नहीं जाहिर किया था और उनकी से उनकी सरकार को खतरा दिख रहा था। 70 सदस्यों की राज्य विधानसभा में केजरीवाल की पार्टी के 62 विधायक हैं। उन्हें तीन चौथाई से भी ज्यादा बहुमत है। फिर भी वह तीसरा मोक्षा है, जबकि उन्होंने विभाग समत बहसित करने का द्वारा रक्षा रखा है। पहले भी उन्होंने एरोप लाया था कि उनके विधायकों को 20 करोड़ रुपए देने की आरोप लाया था कि उनके विधायकों को बाल जारी करने विभागनसभा मत पेश कर दिया। अब फिर आरोप लाया है कि सत्र विभाग को 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश भाजपा ने की है और सरकार गिराया जाता है। दाता की जारी रही है। तब विभाग के टूटूरे से भी केजरीवाल की सरकार पर खिड़ा ही है। कि वे दिल्ली में बयान देने के बाद औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं। किसी व्यक्ति का नाम लें, जिसने पैसे की पेशकश की या कोई फोन नंबर ही बताएं कि उनकी विभागनसभा के सत्र में बजट टाल दिया और विभाग मत पेश कर दिया।

केजरीवाल की कहानियों का अंत नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वामें और उनकी कहानियों का अंत ही नहीं हो रहा है। उनकी सरकार ने एक बार पर विभागनसभा में विभाग सम पेश कर दिया। किसी ने उनके बहुत अधिक विभाग नहीं जाहिर किया था और उनकी से उनकी सरकार को खतरा दिख रहा था। 70 सदस्यों की राज्य विधानसभा में केजरीवाल की पार्टी के 62 विधायक हैं। उन्हें तीन चौथाई से भी ज्यादा बहुमत है। फिर भी वह तीसरा मोक्षा है, जबकि उन्होंने विभाग समत बहसित करने का द्वारा रक्षा रखा है। पहले भी उन्होंने एरोप लाया था कि उनके विधायकों को 20 करोड











